

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2351
जिसका उत्तर 13.03.2025 को दिया जाना है
अमृतसर में राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार

2351. श्री गुरजीत सिंह औजला:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या अमृतसर के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण एक सीमावर्ती शहर, प्रमुख व्यापार केंद्र, प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल होने के कारण यहाँ राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के सुधार, विस्तार, अनुरक्षण और विश्वस्तरीय सड़क अवसंरचना की आवश्यकता काफी महत्वपूर्ण है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का स्वर्ण मंदिर तक एलिवेटेड विमानपत्तन सड़क बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अमृतसर में व्यापार, पर्यटन और स्थानीय परिवहन की उच्च मात्रा को विशेष रूप से देखते हुए सड़क की खराब स्थिति, सुरक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान करने तथा यातायात की भीड़ को कम करने के लिए मुख्य जाँच - परिणाम क्या हैं और इनके समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का अमृतसर सीमा पर परिवहन बाधाओं को सुकर करने और व्यवसायों तथा उद्योग के लिए रसद में सुधार करने के लिए नए एक्सप्रेसवे, बाईपास या एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड) अटकी हुई वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) अमृतसर के महत्व को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने अमृतसर से राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) संपर्कता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। अमृतसर और उसके आसपास शुरू की गई और कार्यान्वित की जा रही कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं में अमृतसर संपर्कता के लिए स्पर सहित दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे, अमृतसर बाईपास (अटारी-वाघा सीमा पर आगंतुकों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए), अमृतसर-रामदास कॉरिडोर एनएच-354 (करतारपुर साहिब आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए), अमृतसर-ऊना कॉरिडोर (अमृतसर को आनंदपुर साहिब से जोड़ता है) और ब्यास-बटाला-डेरा बाबा नानक कॉरिडोर एनएच-503डी (ब्यास को करतारपुर साहिब कॉरिडोर से जोड़ता है) शामिल हैं।

स्वर्ण मंदिर तक एलिवेटेड रोड के निर्माण का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

(ड) सरकार राष्ट्रीय महत्व के कॉरिडोर को समय पर पूरा करने के लिए ऋण भार मुक्त भूमि उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के साथ परामर्श कर रही है। परियोजनाओं की समय-समय पर सभी स्तरों पर समीक्षा की जा रही है।
